राष्ट्रीय सागर | झारखण्ड बुधवार रांची, 05 नवंबर 2014

अस्तित्व का हो रहा है उत्खनन

जसिन्ता केरकेट्टा
स्वतंत्र पत्रकार एवं यूएनडीपी फेलो

आजीविका के साधन हो रहे सीमित

पहाड़िया जनजाति पहाड़ पर रहती है। वे तराई पर लगने वाले साप्ताहिक हाट में बांस, लकड़ी, बरबट्टा बेचते हैं। उनकी आजीविका के मुख्य साधन यही हैं। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 35 किग्रा चावल मिलने का प्रावधान है, लेकिन डीलर या प्रखंड कार्यालय से उन्हें कभी भी पूरा चावल नहीं मिलता है। कई पहाड़ियाओं ने अपना और बच्चों का जीवन बेहतर बनाने के सपने के साथ पत्थर उत्खनन के लिए गैर-पहाड़ियाओं को जमीनें दी थी, लेकिन जमीन देने के बाद उनकी स्थिति और दयनीय हो गई। पत्थरों के उत्खनन के लिए पहाड़ियाओं ने प्रति एकड़ मात्र तीन हजार रूपये सालाना पर अपनी जमीनें दी हैं। एग्रीमेंट के कागजात भी उनको न देकर जमीन लेने वालों ने अपने पास रख लिया है। इससे उनके पास कोई प्रमाण नहीं रह गये हैं। साहेबगंज खनन विभाग के पदाधिकारी अशोक कुमार रजक ने बताया कि जिले में 437 लोगों को पत्थर उत्खनन के लिए जमीन लीज पर दी गई है। मात्र 25 पहाड़िया-संताल आदिवासियों की जमीन पर पत्थर उत्खनन का काम चल रहा है। इस 25 की संख्या में पहाड़ियाओं की संख्या और भी कम दिखाई गई है। इसका अर्थ है 412 लोग गैर-पहाड़िया हैं। पत्थर उत्खनन का काम पहाड़ों पर ही चल रहा और यहां की पहाड़ों की संपति पहाड़ियाओं की है। उनके पास पहाड़ के पट्टे हैं। फिर पत्थर उत्खनन का काम बिना ग्राम-सभा की अनुमती के कैसे गैर-पहाड़ियाओं के हाथों में चला गया है? इसका जवाब प्रशासनिक अधिकारियों के पास नहीं है। हां पूर्व डीसी ए.कुमार मुत्थु ने कहा कि उनका पदस्थापन साहेबगंज में होने के बाद उन्होंने इस दिषा में सख्ती बरती और खनन के लिए लीज देने और रिन्यू करने पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि इस जगह से कुछ दिन पहले ही उनका तबादला हो चुका है। दूसरी ओर खनन-विभाग के एक व्यक्ति ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि जिले में 25000 एकड़ जमीन लीज पर दी गई है। बरहरवा प्रखंड से लेकर मिर्जाचौकी से आगे दूर तक पहाड़ों पर पत्थर उत्खनन का काम चल रहा। देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह 25000 एकड़ से काफी अधिक है। दूसरी ओर, समाजिक कार्यकर्ता प्रेम हेम्ब्रोम का कहना है कि पहाड़ों की 50,000 एकड़ भूमि पर पत्थर उत्खनन का काम हो रहा है, क्योंकि अतिरिक्त 25000 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से खनन जारी है। यह सब प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा है। एसपीटी एक्ट और पेसा कानून, दोनों ताख पर हैं।

पहाड़ियाओं के अस्तित्व का उत्खनन

जिले में आदिम जनजाति पहाड़ियाओं के अस्तित्व का उत्खनन हो रहा, जबकि अनुसूचित जनजातियों के संरक्षक आयुक्त यहां मौजूद हैं। उनके संरक्षण के लिए करोड़ों रूपए आवंटित हो रहे हैं और हालत यह है कि उनके अस्तित्व पर होता उत्खनन रूक नहीं रहा। सबने अपनी आंखें बंद कर ली है। आद्रो पहाड़ के करीब 9 लोगों ने अपनी जमीनें दी हैं। मात्र एक पहाड़ के लोगों ने कुल 375 एकड़ जमीन पत्थर उत्खनन के लिए दी है। वहां विगत 20-25 सालों से खनन हो रहा है, लेकिन जमीन देने वाले पहाड़ियों का जीवन-स्तर सुधरने के बजाय और बिगड़ गया है। आद्रो पहाड़ के आदा पहाड़िया कहते हैं- श् 60 बीघा ;20 एकड़द्ध अर्थात एक पूरा पहाड़ ही गलत तरीके से किसी यादव ;उन्हें सिर्फ यादव ही याद हैद्ध ने ले ली है । षुरू में पांच हजार रुपये देने की बात कही गयी थी, पर मात्र पांच सौ रूपये ही थमा दिया। 20-25 साल से खनन का हो रहा है। जब भी पैसे मांगने जाते हैं, मार पीट कर भगा दिया जाता है। अपराधिक तत्वों के माध्यम से जान से मारने की धमकी भी दी गई है।श् रूपा पहाड़िया कहते हैं - श्मोहन यादव को 29 बीघा ;9.66 एकड़द्ध जमीन दिया है। इस जमीन पर पहले उनका कुरूआ अर्थात खेती-बाड़ी हुआ करती थी । इससे उन्हें सालों भर खाने की कमी नहीं होती थी। यह पहाड़ दस-पंद्रह साल से कोड़ा जा रहा है। वह अब सिर्फ बांस बेचने पर निर्भर हो गए हैं। परिवार का भरण-पोषण मुश्किल से होता है।श् डोम्बे पहाड़िया ने कहा - श् 20 बीघा ;6.66 एकड़द्ध जमीन गई है। उस जमीन पर वह और उसके पूर्वज खेती करते थे। अब खेती-बारी खत्म हो गई है।श् यदि एक पहाड़ के 375 एकड़ में खनन हो रहा है, तो दूसरे पहाड़ों के कुल क्षेत्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रामीणों के अनुसार कभी गंगा पर बने फरक्का ब्रिज से दिखने वाली पहाड़ की उंची चोटियां आज खत्म होने को हैं। इसी तरह तूरी पहाड़िया की 6 बीघा ;2 एकड़द्ध, फगु पहाड़िया की 7 बीघा ; 2.66 एकड़द्ध और प्रधान बोबे पहाड़िया की 3 बीघा ;1 एकड़द्ध जमीन पर पत्थर उत्खनन का काम हो रहा है। गांव के गांव कैसे खत्म हो रहे, बबोनिया गांव इसका उदाहरण है। गांव के प्रधान मईसा पहाड़िया बताते हैं कि बबोनिया गांव में 100 लोग रहा करते थे। आज मात्र एक परिवार के 8 सदस्य बचे हैं। गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में रहने की व्यवस्था कर रहे हैं।

गायब हो रहे हैं झरने व पेड़ों की प्रजातियां

आद्रो पहाड़ पर बसे गांव के प्रधान बोबे पहाड़िया का कहना है गांव वाले खनन को बंद करवाना चाहते हैं क्योंकि उत्खनन का काम उनसे लिए गए जमीन से अधिक बड़े क्षेत्र में हो रहा है। इससे पूरे पहाड़ के पेड़-पौधे खत्म हो रहे हैं। पहाड़ों की नमी भी खत्म हो रही है। जलस्तर नीचे जा चुका है। इससे दूसरों की खेती प्रभावित हो रही है। पेड़ सूखकर मर रहे और पेड़ों की कई प्रजातियां पहाड़ से गायब हो रही हैं। पहले सेम्बल के पेड़ हुआ करते थे, जिसकी रूई काफी कीमती होती है। सेम्बल, व कुसुम के पेड़ अब पहाड़ों से खत्म हो रहे हैं। पहले पहाड़ों पर काफी संख्या में झरने हुआ करते थे, पर अब उनकी संख्या कम हो गई है। पीने का पानी लाने के लिए झरनों की तलाश में कई किलोमीटर दूर जाना होता है। पत्थर उत्खनन से पहाड़ का पूरा जीवन आज अस्त व्यस्त हो गया है। संताल-पहाड़ियाओं के बीच जागरूकता का काम करने वाले शिक्षक सह समाजिक कार्यकर्ता लाओस हांसदा कहते हैं कि राजमहल की पहाड़ियों पर मौजूद जिवाश्मों पर षोध के लिए विदेशों से लोग आते थे। आज पत्थर उत्खनन के कारण यह सब खत्म होता जा रहा है। उत्खनन के दौरान पहाड़ खोखला कर दिया गया है जिससे उपर रहने वाले पहाड़ियाओं को विस्थापित होना पड़ रहा। विस्थापन का बुरा प्रभाव उनके समाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन पर पड़ता है। पहाड़ पर ही जीने वाले पहाड़ियाओं का आश्रय उनसे छिनता जा रहा है। उनका अस्तित्व ही खतरे में है।

पूरे दामिन-इ-कोह में आज सरकारी संरक्षण में एक पूरी जाति के अस्तित्व का ही उत्खनन हो रहा। चंद लोगों के कभी न खत्म होने वाले लालच, स्वार्थ और उपरी पहुंच के कारण एषिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में अपनी पहचान रखने वाली राजमहल की पहाड़ियां और उनपर रहने वाली आदिम जनजाति का अस्तित्व इतिहास बन जाने को है, चूंकि पहाड़िया किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सषक्त वोट बैंक नहीं हैं इसलिए आज तक किसी के लिए यह कोई गंभीर मुद्दा नहीं बन सका है।

समाप्त